

संपादकीय

नाइंसाफी करता बुलडोजर

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को असंवेधानिक करार दिया है, बावजूद इसके महाराष्ट्र और यूपी में ऐसी कार्रवाइयाँ जारी हैं। बिना उचित सुनवाई दिए मकान गिराए जा रहे हैं, जो नागरिक अधिकारों का उल्लंघन है। प्रशासन की लापरवाही के चलते अवैध निर्माण रोकने में असफलता नजर आती है।

बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर तल्ख टिप्पणी करनी पड़ी है। हैरत की बात है कि देश की शीर्ष अदालत के बार-बार कहने के बावजूद, महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक बुलडोजर के जरिये कथित इंसाफ की कोशिश जारी है, जबकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने जिस घटना पर कहा कि यह उसकी अंतरात्मा को झकझोर देने वाली है, वह प्रयागराज की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नोटिस देने के 24 घंटे के भीतर उनके मकान गिरा दिए गए। इसी तरह, महाराष्ट्र के मालवण में एक कबाड़ व्यापारी के घर पर ++ बुलडोजर चलाने के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय नगर परिषद को नोटिस जारी किया है। लेकिन सबसे ज्यादा चौकाती है नागपुर की घटना, जहां हाल में घटी हिंसा के आरोपियों के घर नगर निगम ने ध्वस्त करा दिए।

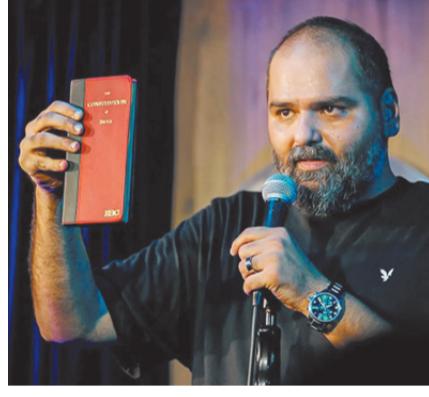
हर जगह पुलस-प्रशासन के काम करने का तराका एक जसा दख्ता है। जिस भी मामले से बड़े जनसमुदाय की भावनाएं जुड़ी होती हैं, उनमें फटाफट आरोपियों की संपत्ति की नाप-जोख शुरू हो जाती है। एक दिन नोटिस जारी होता है और अगले दिन बुलडोजर पहुंच जाता है अपील करने तक का मौका नहीं दिया जाता, जो हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। नागपुर मामले में ही बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बैंच ने आरोपियों की प्रॉपर्टी के खिलाफ कार्बाई पर रोक लगादी, लेकिन जब तक आदेश आता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रशासन का तर्क है कि निर्माण अवैध था। लेकिन क्या बिना उन्नित

प्रशासन का तक हक्क निमाण अवधि थी। लोकन, क्या बिना अधिक सुनवाई के कार्रवाई करना वैध है? जो अवैध निर्माण बरसों से खड़ा है, जिस पर किसी अथर्विटी की नजर नहीं जाती, अचानक वह इतना खतरनाक हो जाता है कि आनन-फानन में बुलडोजर चलाना पड़ता है। ऐसी ही तेजी सारे अवैध निर्माणों के खिलाफ क्यों नहीं दिखती? और इससे भी बड़ा सवाल है कि इतना बड़ा अवैध निर्माण हो कैसे जाता है? सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में कहा था कि दंडात्मक उपायों के रूप में बुलडोजर कार्रवाई असंवेधानिक है एक्शन से पहले नोटिस और सुनवाई का वक्त देना होगा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश का उल्लंघन करने वाले अफसरों पर कार्रवाई तक की चेतावनी दी थी, लेकिन इसका असर होता नहीं दिख रहा और होगा भी क्यों, जब सरकारें खुद इसे प्रमोट करेंगी। इस पर रोक लगनी चाहिए।

हरीश शिवनानी अपने कॉमेडी शो में की रक्षा के लिए फतेह के साथ धक्का मारकी कर

.....

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के तरफ संकेत कर जो कुछ कहा है, उसे समझना, उसके निहितार्थ निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। यह महज कॉमेडी नहीं, विशुद्ध रूप से फूहड़ तरीके का राजनीतिक वक्तव्य है, किसी का सार्वजनिक अपमान, उसकी सम्पत्ति है। शास्त्र में दूसरे दृष्टि



मानहान हा भारत म दल-बद्धासिल करने का लंबा राजनीतिक है। 1977 और 1979 में मुख्यमंत्री भजनलाल के समूची कैद दलबदल करने का इतिहास तो जहाँ ही, राजनीतिक मुहावरा आयाराम हरियाणा के एक विधायक की ही

अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता की अनुमति नहीं भूलना चाहिए जो सुसंस्कृत, मर्यादित और शिष्ट बुनियाद होते हैं। इस समाज में निरंकुश कुछ भी नहीं होता। मर्यादाओं की एक सीमा-रेखा होती है जिससे सर्वधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1)(क) के तहत नागरिकों को हालांकि यह भी असीम नहीं है। 19(2) के तहत कुछ उचित प्रतिबंध रखा गया है। हर अभिव्यक्ति अराजकता नहीं हो सकता। लोकतंत्र

दिनों महरंग बलूच को हिरासत में ले लिया। दरअसल, बीएलए के लगातार बढ़ते हमलों के बाद पाक सरकार ने शांतिपूर्ण आंदोलन का दमन तेज कर दिया है, जिसकी चपेट में शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने वाली मानवाधिकार कार्यकर्ता

डॉ. महरंग भी आई है। उल्लेखनीय है कि महरंग के पिता अब्दुल गफकार लैंगोव एक राष्ट्रवादी बलूच नेता थे। वर्ष 2009 में उनका सुरक्षा बलों ने अपहरण कर लिया था। जिसके तीन साल बाद उनकी लाश बुरी स्थिति में मिली थी। लेकिन आज महरंग पाक दमन के खिलाफ एक मुखर आवाज बन चुकी है। बहराल, हाल के बीएलए के एक के बाद एक बड़े हमलों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। खासकर, हालिया ट्रेन अपहरण के मामले ने, जिसने

वाचिक औं
शान्दिक हिंसा पर
भी अंकुश उतना है
जरूरी है जितना
दैहिक हिंसा पर
भारतीय बौद्धिक
जगत की दिक्कतें
यह भी कम नहीं
कि उसके
बौद्धिकता किसी
व्यक्ति, समूह,
जाति, समुदाय के
परखने, उसका

मल्लाकन करन या उसक पक्ष-विपक्ष में खड़े होने के मूल में उसके पैमाने, उसके निकष मापदंड उसकी विचारधारा के अनुरूप बदलते रहते हैं। इसके मूल में उसकी राजनीतिक विचारधारा, उसकी अपेक्षाएं, उसके महत्वाकांक्षाएं और उसके निहितार्थ मुख्य भूमिका निभाते हैं। ऐसा ही कामरा के प्रसंग में हुआ है। कला और साहित्य-संस्कृति के स्वायत्तता के स्वयंभू टेकेदारों ने अपने स्तर पर एक पैमाना बना रखा है जिससे वे अभियक्षित की आजादी की हद तय करते हैं। सच यही है कि आज भारतीय बौद्धिक जगत अपनी इस खामोशी की वज़ह ज्यादा अविश्वसनीय और बदनाम है जिसे निर्मल वर्मा ने चुनी हुई चुप्पी कहा था, जिसे सामाज्यतः सलेक्टिव खामोश कहा जाता है ऐसे चुनी हुई चुप्पियों वाले कथित और स्वयंभू बुद्धिजीवियों की अभिव्यक्ति के आजादी तब खतरे में नहीं आती जब तस्लीम नसरीन को बोलने से रोका जाता है, तारेव

ल, बलूचिस्तान के लोगों
न बन चुकी, नई पीढ़ी की
ग की गिरफ्तारी पाक
की हताशा का ही नतीजा
में पाक सेना व खुफिया
रा पिटा की हत्या के बाद
प्रतिरोध की आवाज बनने
किया था। पिटा की मौत
पुरक्षा बलों ने उनके भाई
2017 में डेढ़ लिया था।
वीन माह तक हिरासत में
उत्तराएं देने के बाद छोड़ा
के बाद महरंग ने तय
वह गैरकानूनी रूप से
उठाने और उनकी हत्या के
निर्णायक लडाई लड़ेंगी।
उत्तर तरह-तरह के प्रतिबंध
न हैं, उन्हें गिरफ्तार किया
को तैयार नहीं हैं। वे कहती
बलूच लोग बिना अत्याच
स्वाधिमान से जीना चाहते हैं
हिंसा व भय से मुक्ति चाहते
हजारों लोगों के गायब हो
सिलसिला अब बंद होना चाहता

दरअसल, बलूच
पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्र
यह प्रांत पाक का 44 फीसदी
भाग रखता है। यह गैस, स
तांबा आदि दुर्लभ खनियां
प्राकृतिक संसाधनों से भरा
जिस पर चीन समेत दुनिया वे
की नजर है। वास्तव में जब
विभाजन हुआ तो पाक हुक्म
बलूचिस्तान के कबाइली नेता
स्वायत्ता देने का वायदा
लेकिन बाद में राष्ट्रवादी

बाहर किया जाता है। इस आजादी पर तब भी खतरा नहीं आता जब जेएनयू के वामपंथी योग्य शिक्षक रामदेव को किसी कार्यक्रम में बुलाने का विरोध कर उनका कार्यक्रम रद्द करवा देते हैं या नूपुर शर्मा की तथ्यात्मक बात के बावजूद वे चुप्पी धारण कर लेते हैं। यदि कोई अपनी वैचारिकता के निकट है तो गलत होकर भी सही, वरना विरोधी होने पर खामोशी। क्या एक लोकतांत्रिक देश में सलेक्टिव चुप्पी और सलेक्टिव स्वस्थ प्रवृत्ति है?

कुणाल कामरा का विवाद से पुराना नात रहा है। वरिष्ठ पत्रकार अर्नन्द गोस्वामी से लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संदर्भ में वो विवादों में रह चुके हैं। नए बीडियो में कामरा ने मुकेश अंबानी के बेटे का उसके वजन के लिए मजाक उड़ाया है। सभी जानते हैं कि अनन्त अंबानी को बीमारी की वजह से स्टेरोइंड्स लेने पड़ते हैं स्टेरोइंड्स के साइड इफेक्ट की वजह से उनके ये वजन बढ़ा हुआ है। यानी बीमारी की वजह से अनन्त अंबानी की ये हालत है और कोई उसका मजाक उड़ा रहा है तो ये कुछ भी हो सकता है, कॉमेडी तो नहीं। वास्तविकता यह है कि आज के दौर में जब कॉमेडियन का मार्केट ठंडा हो जाता है तब वापस मार्केट में चर्चा में आने के लिए धर्म, राजनीतिक, जाति आदि विषयों पर निजी रूप से व्यंग्य करते हैं ताकि विवाद हो और वह फिर चर्चा में आ जाएं। पैसे और चर्चा में बने रहने के लिए उनका एक तरह का पेशा है। इसे आप इस प्रकरण से भी समझ सकते हैं कि इस विवाद के बाद सुपर थैंक्यू के नाम पर कामरा को दो दिन में ही लाखों रुपये की फंडिंग हो चुकी है।

न्याय का सवदनशालता

न्याय का सवदनशालता

पिछले दिनों पूरे देश में सवालों के घेरे में था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाकर न्याय की संवेदनशीलता को संबल दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को लेकर महिला संगठनों व बौद्धिक वर्गों में तल्ख प्रतिक्रिया देखी जा रही थी। यहां तक कि महिला संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था। शीर्ष अदालत के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने माना कि फैसला न केवल असंवेदनशील है बल्कि अमानवीय नजरिया भी दर्शाता है। जिसके चलते इस फैसले पर रोक लगाना आवश्यक हो जाता है।

बेंच ने माना कि फैसला लिखने में संवेदनशीलता की कमी

बृथ न माना कि कसला लेखन म सपदनरातों का कमा दृष्टिगोचर होती है। कोर्ट का मानना था कि जब फैसला चार माह तक सुरक्षित रखने के बाद सुनाया गया तो यह नहीं कहा जा सकता कि इस पर गंभीर मंथन नहीं हुआ। वर्ही शीर्ष अदालत ने इस मसले पर केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया है। उल्लेखनीय है कि सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की निंदा की।

दरअसल, विवाद इस बात का लकर हुआ था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि पीड़िता किशोरी के स्तनों को छूना व पायजामे की डोरी तोड़ना बलात्कार या बलात्कार की कोशिश नहीं माना जा सकता। उत्तेजनीय है कि यह मामला उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद के पटियाली थाना क्षेत्र में एक किशोरी से जुड़ा था, जिसके बाबत जस्टिस राममनोहर नारायण मिश्रा ने यह विवादित फैसला दिया था। इस एकल पीठ का कहना था कि मामले में तथ्यों व आरोपों के आधार पर तय करना संभव नहीं है कि बलात्कार का प्रयास हुआ था। जिसके लिये अभियोजन पक्ष को सिद्ध करना था कि अभियुक्तों का यह कदम अपराध करने की तैयारी के लिये था। दरअसल, इसी के मद्देनजर देश में फैसले के खिलाफ तल्ख प्रतिक्रिया देखी गई। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ का कहना था कि दुराचार करने की कोशिश और अपराध की तैयारी के बीच के अंतर को सही ढंग से समझना चाहिए।

हुए हैं। ऐसे में दमन व अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाली बलूचिस्तान की शेरनी महरंग बलूच को गिरफ्तार करने की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने निंदा की है। सवाल बलूचों की आवाज दबाने को लेकर भी उठ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि दुनिया की चर्चित टाइम मैगजीन ने महरंग को दुनिया के सौ उभरते नेताओं में शामिल किया है। महरंग को तब गिरफ्तार किया गया था जब वे क्वेटा में दमन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। उन पर देशद्रोह व आतंक फैलाने जैसे आरोप लागए

गए हैं। उनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे कुछ प्रदर्शनकारी भी इस कार्रवाई के दौरान मारे गए। बलूच यकजेहती कमेटी के तत्वावधान में आंदोलन की अगुआ बनी महरंग बलूच की गिरफ्तारी के खिलाफ बलूचिस्तान में तीखी प्रतिरोध का प्रतीक बनता जा रहा है। विश्वविद्यालयों से निकलने वाले छात्र बलूच आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। पाक के दमन के बावजूद उनके प्रतिरोध के सूर मुख्खर हो रहे हैं। इतना ही नहीं जैसे-जैसे पाक सेना व खुफिया एजेंसियों का